ओडिशा में आर्थिक और वित्तीय विकास*

दीपक मोहंती

मैं श्री विजय केतन मिश्रा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने का अवसर दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दि पॉलिटिकल और बिज़नेस डेली ने ओडिशा के विकास में बैंकिंग की भूमिका विषय को चुना है। वित्तीय क्षेत्र के विकास में बैंकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्त-पोषण से वृद्धि होती है और जिसके चलते आर्थिक प्रगति आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र के विकास में सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। तथापि, हमने औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का दायरा बढ़ाने और समाज के लोगों की स्थिति सुधारने के लिए वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दिशा में अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाया है।

आज की अपनी इस चर्चा में, मैं राज्य की आर्थिक और वित्तीय संरचना की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने के साथ-साथ विशेष रूप से ओडिशा में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न वित्तीय समावेशन के प्रयासों का उल्लेख करूंगा। निष्कर्ष रूप में, मैं आने वाली नीतिगत चुनौतियों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा।

देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.7 प्रतिशत हिस्सा और देश की जनसंख्या का 3.5 प्रतिशत हिस्सा वाला राज्य ओडिशा राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इतिहास में ज्यादा न जाकर मैं बीसवीं सदी के प्रारंभ से हुए आर्थिक विकास के संबंध में मुख्य रूप से चर्चा करूंगा क्योंकि यह एक ऐसा समय है जिसमें भारतीय अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह वृद्धि ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में देखी गई।

आर्थिक संरचना

2003 से 2008 तक के 5 वर्ष की अवधि के दौरान अखिल भारतीय सकल देशी उत्पाद संवृद्धि दर प्रति वर्ष औसतन 8.7 प्रतिशत रही। तदुपरांत 2009-12 तक के 4 वर्ष की अवधि में यद्यपि अखिल भारतीय सकल देशी उत्पाद संवृद्धि दर वैश्विक वित्तीय संकट के चलते गिरकर प्रतिवर्ष 7.6 प्रतिशत रह गई, फिर भी इसे उच्च माना जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस उच्च संवृद्धि चरण के अनुरूप ओडिशा की अर्थ-व्यवस्था ने अपने सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) की दर में वृद्धि की है। वस्तुतः, 2003-08 की प्रारंभिक अवधि में ओडिशा में औसत जीएसडीपी संवृद्धि प्रतिवर्ष 11.6 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय औसत दर से काफी अधिक थी। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप ओडिशा की संवृद्धि दर कम होकर प्रतिवर्ष 7.6 प्रतिशत रह गई (चार्ट 1)।

इस संवृद्धि की गतिकी में, तीन महत्त्वपूर्ण पक्ष निकलकर सामने आए हैं, पहला, 2003-08 के प्रारंभिक चरण में संवृद्धि मुख्यतः उद्योग के चलते हुई थी। दूसरा, 2009-12 के बाद के चरण में संवृद्धि सेवा क्षेत्र के चलते हुई, तीसरा, इन दोनों चरणों के दौरान कृषि संवृद्धि कम और स्थिर बनी रही (चार्ट 2)।

विभिन्न स्तरों पर 2002-12 के दशक के दौरान संवृद्धि में तेजी पंजीकृत विनिर्माण, निर्माण, खनन और उत्खनन और व्यापार तथा होटल के कारण हुई (चार्ट 3)।

चार्ट 1 : वार्षिक संवृद्धि प्रवृत्ति

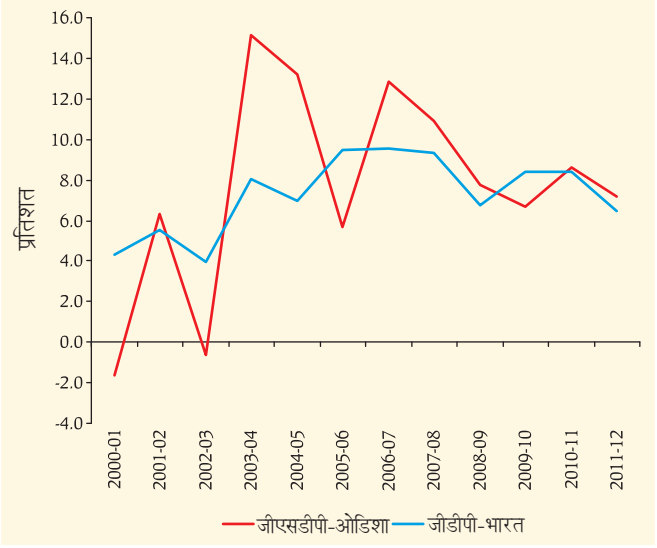

* 20 अगस्त 2012 को ओडिशा के विकास में बैंकों की भूमिका पर दि पॉलिटिकल ऐंड बिज़नेस डेली, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित सेमीनार में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती द्वारा दिया गया भाषण। इस भाषण को तैयार करने में पी.के. नायक, रेखा मिश्रा, वाई.के.गुप्ता, दीपा राज और एस. सूरज ने सहयोग दिया।

चार्ट 2 : क्षेत्रवार संवृद्धि प्रवृत्ति: ओडिशा

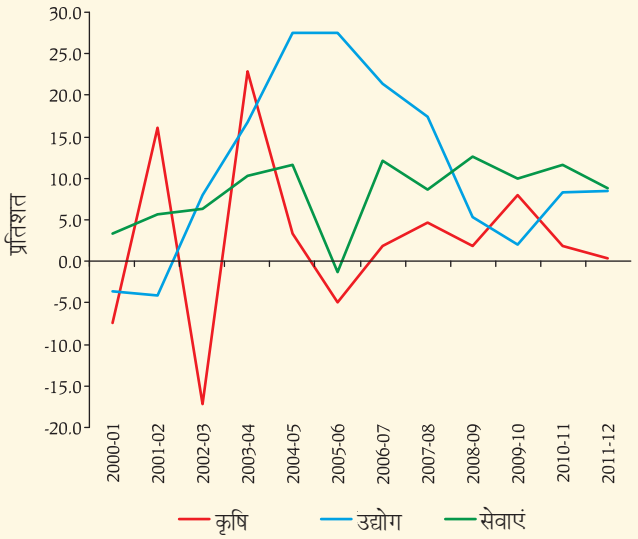

चार्ट 3 : ओडिशा की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रगत प्रेरक कारक

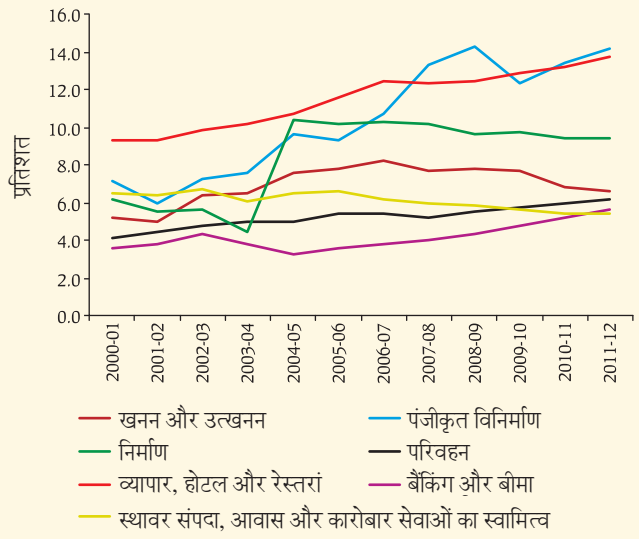

अलग-अलग संवृद्धि प्रवृत्तियां जीएसडीपी के क्षेत्रों में संघटनात्मक परिवर्तन को दर्शाती हैं: कृषि के हिस्से में लगातार गिरावट आई; उद्योग के हिस्से में पहले बढ़ोतरी हुई फिर गिरावट आई और सेवाओं के हिस्से में पहले बढ़ोतरी हुई फिर गिरावट आई। ओडिशा की अर्थव्यवस्था के इस संरचनात्मक बदलाव, जो मोटे तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति के अनुकूल हैं, में उद्योग के हिस्से में हुई बढ़ोतरी उल्लेखनीय है (चार्ट 4)।

ओडिशा में हुई प्रारंभिक संवृद्धि के चलते राष्ट्रीय जीडीपी 2002-03 में 2.3 प्रतिशत के जीएसडीपी से बढ़कर 2008-09 में 2.7 प्रतिशत हो गई। जैसे-जैसे जीएसडीपी की संवृद्धि दर धीमी हुई और राष्ट्रीय स्तर की ओर अभिमुख हुई, यह हिस्सा भी कम हो गया किन्तु 2008-09 के बाद लगातार लगभग 2.6 प्रतिशत बनी रही। तथापि, सबसे अधिक उल्लेखनीय प्रभाव वास्तविक प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (2004-05 के मूल्यों पर) में 2002-03 के 13,923 से बढ़कर 2010-11 में ₹25,708 के रूप में देखा जा सकता है। इसी वजह से प्रति व्यक्ति आय के संबंध में राज्यों के बीच ओडिशा की स्थिति में सुधार हुआ और यह 2002-03 के नीचे से तीसरे क्रम से सुधरकर 2010-11 में सातवें क्रम पर

चार्ट 4 : संवृद्धि की क्षेत्रवार संघटना

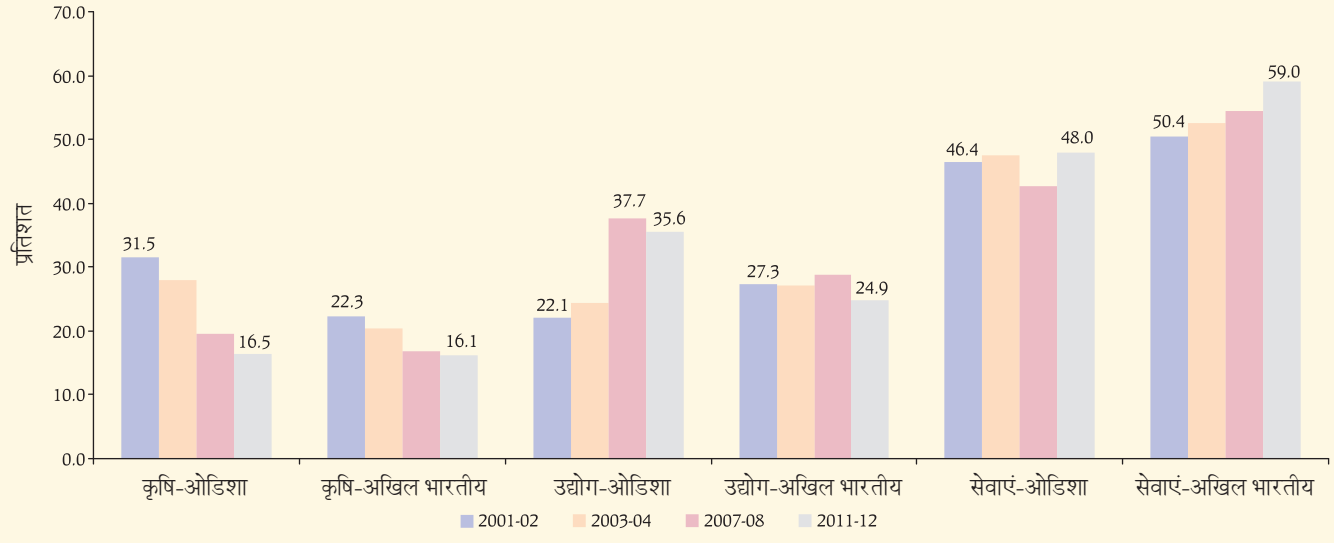

चार्ट 5 : प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय विचलन : 2010-11

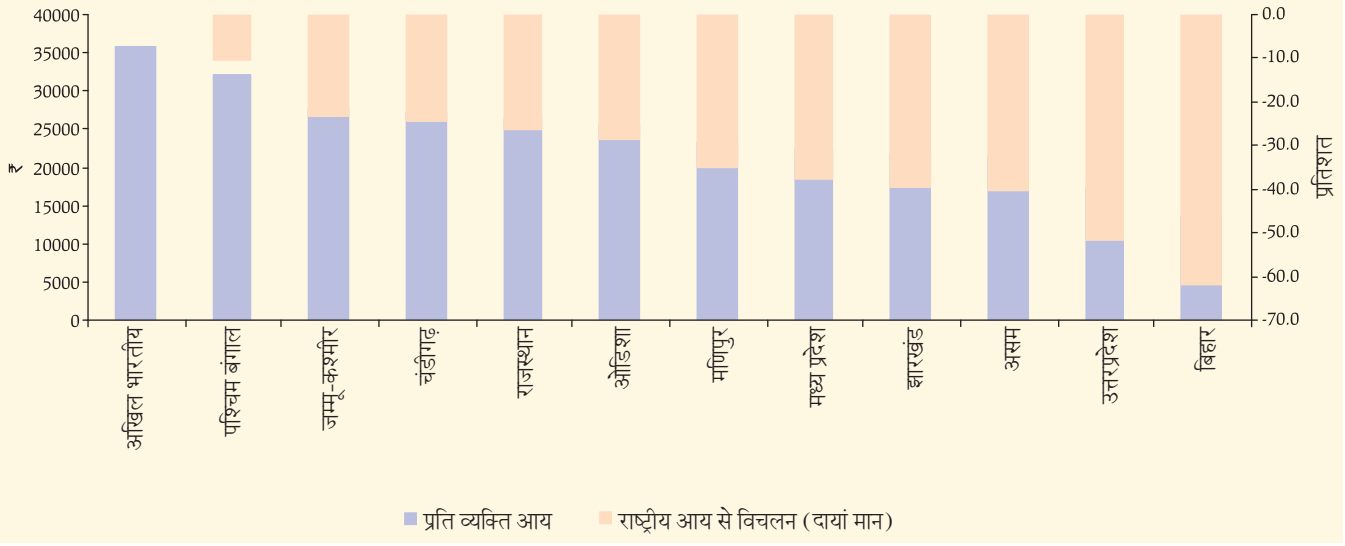

आ गया। इस प्रगति के बावजूद, ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है (चार्ट 5)।

जहाँ, अर्थव्यवस्था उद्योग और सेवाओं की ओर अंतरित हो रही है, वहीं श्रम शक्ति कृषि में लगी हुई है। 2010-11 में कृषि और वानिकी में श्रम में हिस्से का लगभग 52 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य में 59 प्रतिशत का उच्चतर श्रम हिस्सा लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त, विनिर्माण गतिविधियों में बढ़ोतरी के बावजूद, श्रम शक्ति में विनिर्माण का हिस्सा राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम बना हुआ है (सारणी 1)। इसके अलावा, 2010-11 में लगभग 50 प्रतिशत की श्रम शक्ति सहभागिता दर, राष्ट्रीय स्तर के 53 प्रतिशत की श्रम शक्ति सहभागिता दर की तुलना में कम थी।

कृषि में श्रम शक्ति के अधिक लगे रहने के बावजूद, कार्यशील आयु वाली जनसंख्या की अधिक संख्या के कारण ओडिशा की जनसांख्यिकी संरचना संवृद्धि की दिशा में समुचित अवसर प्रदान करती है (चार्ट 6)। इसलिए, राज्य के लिए प्रमुख चुनौती यह है कि वह उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार पैदा करे ताकि कम उत्पादकता वाली कृषि गतिविधियों से श्रम शक्ति को हटाया जा सके। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक व्यय करने के साथ-साथ श्रम शक्ति की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत होगी। इस संबंध में, उच्च शिक्षा

सारणी 1 : विस्तृत उद्योग समूह द्वारा रोजगार का हिस्सा
(सामान्य प्रमुख स्थिति)

(प्रतिशत)

गतिविधि	2010-11	
	ओडिशा	अखिल भारतीय
कृषि और वानिकी	58.8	52.2
खनन और उत्खनन	0.6	0.7
विनिर्माण	6.5	10.6
बिजली	0.3	0.4
निर्माण	11.2	8.7
व्यापार	8.1	7.7
परिवहन और भंडार	2.0	3.5
वित्त और बीमा	0.6	1.0
समुदायिक सेवाएं	8.0	8.4
अन्य	3.9	6.8
सभी	**100**	**100**

स्रोत : श्रम ब्यूरो, भारत सरकार

चार्ट 6 : जनसंख्या का आयु समूह-वार वितरण

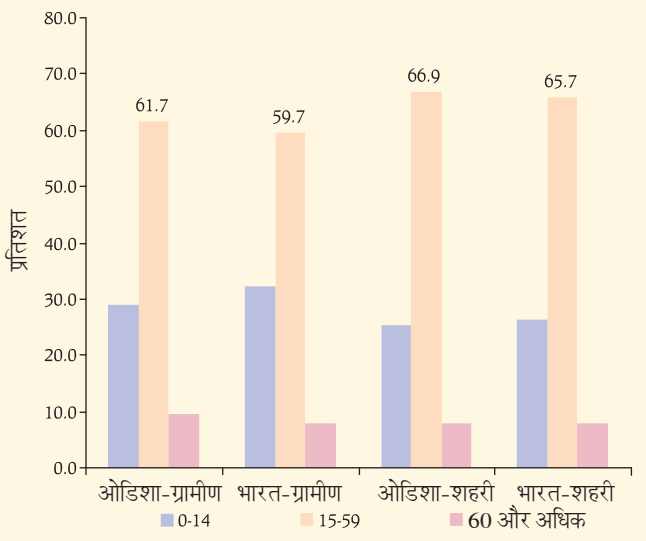

और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के सरकारी प्रयासों में निजी क्षेत्र संपूरक की प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है।

सामाजिक संकेतक

हाल के वर्षों में तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद ओडिशा मानव विकास में निम्न स्तर पर बना रहा। कम शहरीकरण, कम प्रति व्यक्ति आय, गरीबी की अधिकता, नवजात शिशुओं की अधिक मृत्यु दर और राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम जीवन प्रत्याशा दर के कारण ओडिशा मानव विकास सूचकांक - 2007-08 के अनुसार 23राज्यों[1] में 22वें स्थान पर है (चार्ट 7)।

पीने का स्वच्छ पानी और बिजली जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं तक पहुँच वाले परिवारों का हिस्सा राष्ट्रीय औसत की तुलना में सापेक्ष रूप से काफी कम रहा है, यद्यपि, 2001 और 2011 के दशक के बीच इनमें पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार, टेलीवीज़न, टेलीफोन और यांत्रिक वैयक्तिक परिवहन जैसी घरेलू आस्तियों का स्वामित्व राष्ट्रीय औसत से कम है। यद्यपि, बैंकिंग सुविधा रखने वाले परिवारों की जनसंख्या में सुधार हुआ हैं, फिर भी यह राष्ट्रीय औसत से अभी भी कम है (सारणी 2)।

राज्य वित्त

राज्य के वित्त में पर्याप्त सुधार हुआ क्योंकि ओडिशा ने निर्धारित समय-सीमा से पहले ही राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान में दिए गए

चार्ट 7 : मानव विकास संकेतक

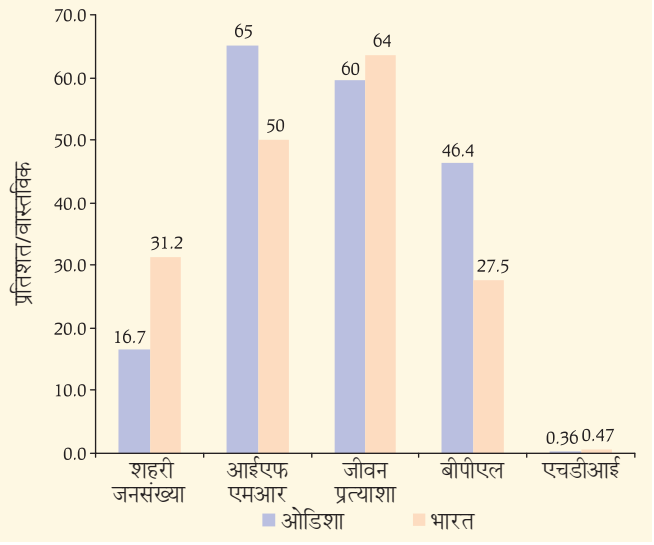

[1] असम को छोड़कर उत्तरी-पूर्वी राज्यों को एक माना गया और इसलिए भारत सरकार की भारत मानव विकास रिपोर्ट-2011 में मात्र 23 राज्यों की एचडीआई रैंकिंग से तुलना की गई।

सारणी 2 : जीवन संकेतकों का मानक

(परिवार के प्रतिशत के रूप में)

वर्ग	ओडिशा		अखिल भारतीय	
	2001	2011	2001	2011
	बुनियादी सुविधाएं			
परिसर में पीने का पानी	19.0	22.4	39.0	46.6
बिजली	26.9	43.0	55.9	67.3
परिसर में शौचालय सुविधा	14.9	22.0	36.4	46.9
	आस्तियां			
टेलीवीज़न	15.5	26.7	31.6	47.2
कम्प्यूटर	–	5.1	–	9.5
टेलीफोन	3.9	39.8	9.1	63.2
दोपहिया वाहन	7.9	14.5	11.7	21.0
चार पहिया वाहन	1.1	1.8	2.5	4.7
	सुविधाएं			
बैंकिंग	24.2	45.0	35.5	58.7
	परिवार			
परिवार (मिलियन में)	7.9	9.7	192.0	246.7

स्रोत : जनगणना 2011, भारत सरकार

लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। 2005-06 में राजस्व खाते में बढ़ोतरी हुई साथ ही 2006-07 में राजस्व अधिशेष में अधिक रहा। यद्यपि, 2008-09 के दौरान ओडिशा की वित्तीय स्थिति में थोड़ी गिरावट आई जो समष्टि आर्थिक गिरावट और छठवें वेतन आयोग एवार्ड के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है, तबसे यह समेकन के रास्ते पर वापस आ गया है। राजस्व अधिशेष और कम राजस्व अधिशेष के कारण बाजार ऋण की आवश्यकता कम पड़ी। वास्तव में, 2006-07 से राज्य बाजार से उधार लेने से परहेज कर रहा है। इसका राज्य वित्त पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि राज्य की बकाया देयता मार्च 2008 के जीएसडीपी के 33.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2012 में 21.1 प्रतिशत रह गई जो मार्च 2013 तक और घटकर 19.6 होने की संभावना है।

देयताओं में कमी के चलते ऋण-भुगतान लागत में पर्याप्त कमी हुई है, जिससे उच्च पूंजी व्यय और सामाजिक व्यय के लिए अवसर मिला है। सामाजिक और आर्थिक ढांचा सुधारने के लिए विकास चुनौतियों को ध्याने में रखते हुए राज्य के लिए यह जरूरी है कि वह ऋण लिए बिना पूंजीगत परिव्यय बढ़ाने के लिए अपना स्वयं का कर राजस्व जुटाने के लिए उपाय करे (सारणी 3)।

सारणी 3: ओडिशा की राजस्व स्थिति

(जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशत के रूप में)

मद	2004-08	2008-12	2012-13
1. राजस्व प्राप्तियां	16.9	17.1	16.9
1.1 निजी कर राजस्व	5.7	5.7	6.0
1.2 चालू अंतरण	9.1	9.2	8.9
2. राजस्व व्यय	15.0	15.5	15.9
2.1 विकासगत राजस्व व्यय	7.8	9.9	9.6
2.2 ब्याज भुगतान	3.4	1.8	1.7
3. पूंजी परिव्यय	1.8	2.4	2.7
4. सामाजिक व्यय	6.2	8.2	7.8
5. राजस्व घाटा	-1.3	-1.9	-0.9
6. सकल वित्तीय घाटा	0.4	0.6	1.8
7. प्राथमिक घाटा	-3.0	-1.3	0.1
8. देयताएं (अंतिम बिन्दु)	33.8	21.1	19.6

नोट : (-) चिह्न अधिशेष का संकेत करता है।
स्रोत : राज्य सरकार का बजट दस्तावेज।

चार्ट 8 : बैंकिंग व्याप्ति की प्रवृत्तियां

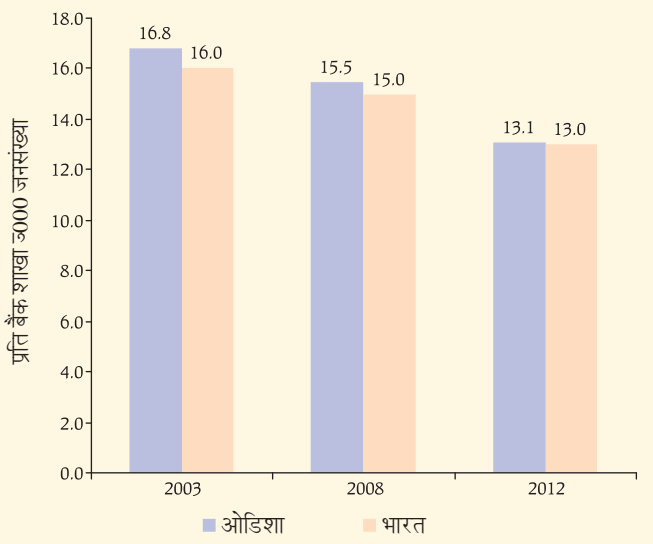

बैंकिंग विकास

अब मैं राज्य में बैंकिंग विकास के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। भारत में औपचारिक वित्तीय प्रणाली का परिचालन प्रमुख रूप बैंकों द्वारा किया जाता है और यही बात ओडिशा पर भी लागू होती है। ओडिशा में औसत जनसंख्या प्रति बैंक शाखा, मार्च 2003 के 16,800 से घटकर मार्च 2011 में 13,800 हो गई जो कि लगभग राष्ट्रीय औसत के 13,400 के आस-पास है (चार्ट 8)। इस अवधि के दौरान वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की संख्या 2,240 से बढ़कर 3,234 हो गईं।

शाखा नेटवर्क और इसकी जनसंख्या कवरेज के अतिरिक्त, बैंकिंग विकास के अन्य प्रमुख संकेतक ऋण-जमा (सीडी) अनुपात है। 2001 के पिछले दशक के दौरान ओडिशा का सीडी अनुपात 42 प्रतिशत रहा, जो राष्ट्रीय औसत के 54 प्रतिशत से कम था। जैसे ही राज्य में तीव्र आर्थिक वृद्धि हुई, सीडी अनुपात में न केवल वृद्धि हुई बल्कि यह राष्ट्रीय औसत से भी अधिक हो गया और 2005-06 में यह 79 प्रतिशत हो गया। इसके बाद सीडी अनुपात में गिरावट आई विशेष रूप 2007-08 के बाद जब वृद्धि धीमी पड़ गई। मार्च 2011 के अंत में, ओडिशा का सीडी अनुपात 56 प्रतिशत रहा जो कि राष्ट्रीय औसत के 76 प्रतिशत की तुलना में काफी कम था (चार्ट 9)।

ऋण व्यापन का अन्य संकेतक जीएसडीपी अनुपात की तुलना में ऋण है। ओडिशा का यह अनुपात भी काफी कम है जो

चार्ट 9 : ऋण-जमा अनुपात की प्रवृत्ति : ओडिशा

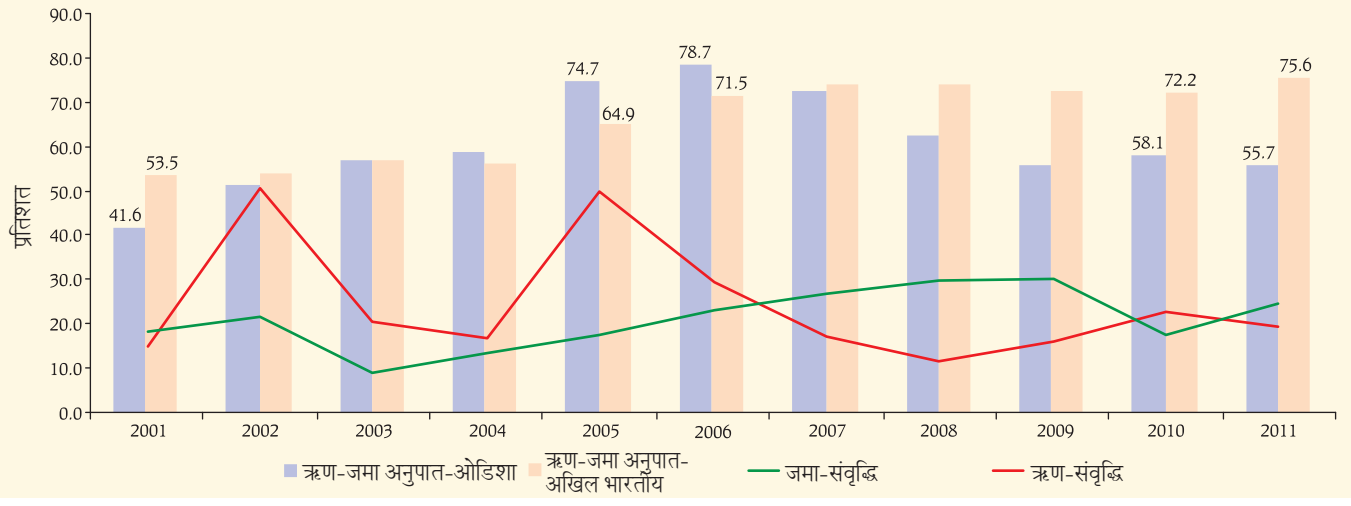

चार्ट 10 : ओडिशा में ऋण-विस्तार

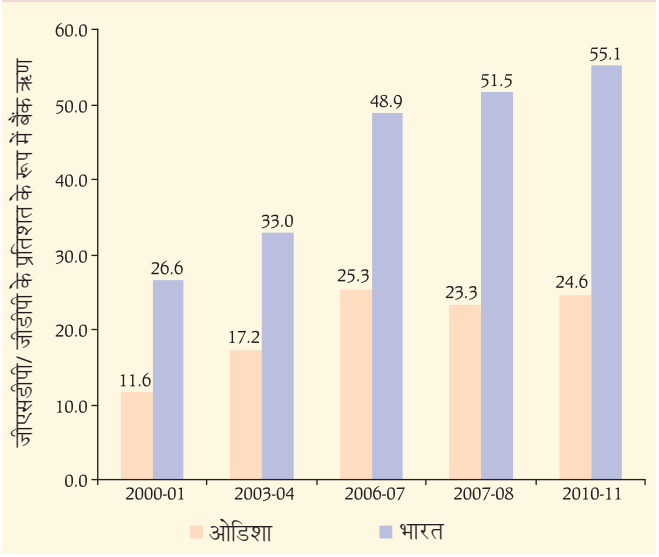

राज्य में और अधिक बैंकिंग विकास की संभावना पर जोर देता है (चार्ट 10)।

न सिर्फ सीडी अनुपात में कमी आई, बल्कि हाल के वर्षों के दौरान ऋण विनियोजन में जिलों के बीच अन्तर-क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी है जो अपेक्षाकृत कम विकसित जिलों में विनियोजन करने की आवश्यकता पर बल देता है (चार्ट 11)।

चट्टोपाध्याय (2011) ने वित्तीय समावेशन से संबंधित एक संयुक्त सूचकांक की बात की है जिससे पता चलता है कि 2009-10 में 0.33 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में ओडिशा का 0.20 का कम अनुपात था जिससे 23 राज्यों में ओडिशा 16वें स्थान पर रहा[2]। क्षेत्रवार विश्लेषण ने पता चलता है कि यद्यपि, ओडिशा की कुल जनसंख्या का 83 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है किन्तु कृषि में ऋण-प्रवाह अन्य क्षेत्र की तुलना कम है।

वित्तीय समावेशन

इस पृष्ठभूमि के विपरीत, अब मैं भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय समावेशन की रणनीति के बारे में और रिज़र्व बैंक द्वारा ओडिशा के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं? पर चर्चा करना चाहता हूँ। समावेशी विकास के लिए गरीब और समाज के वचित वर्ग को बैंकिंग से जोड़ना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, हमारे हाल के वित्तीय समावेशन की मुहिम में चार प्रमुख तत्व शामिल किए गए हैं।

पहला, कमजोर और वित्तीय दृष्टि से नहीं शामिल किए गए वर्गों के लिए मूलभूत वित्तीय उत्पाद बनाने का प्रावधान। इसमें नो फ्रिल खाते के रूप में बचत-सह-ओवरड्राफ्ट उत्पाद और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के रूप में उद्यमी ऋण शामिल है।

चार्ट 11 : ओडिशा में क्षेत्रीय ऋण असमानता

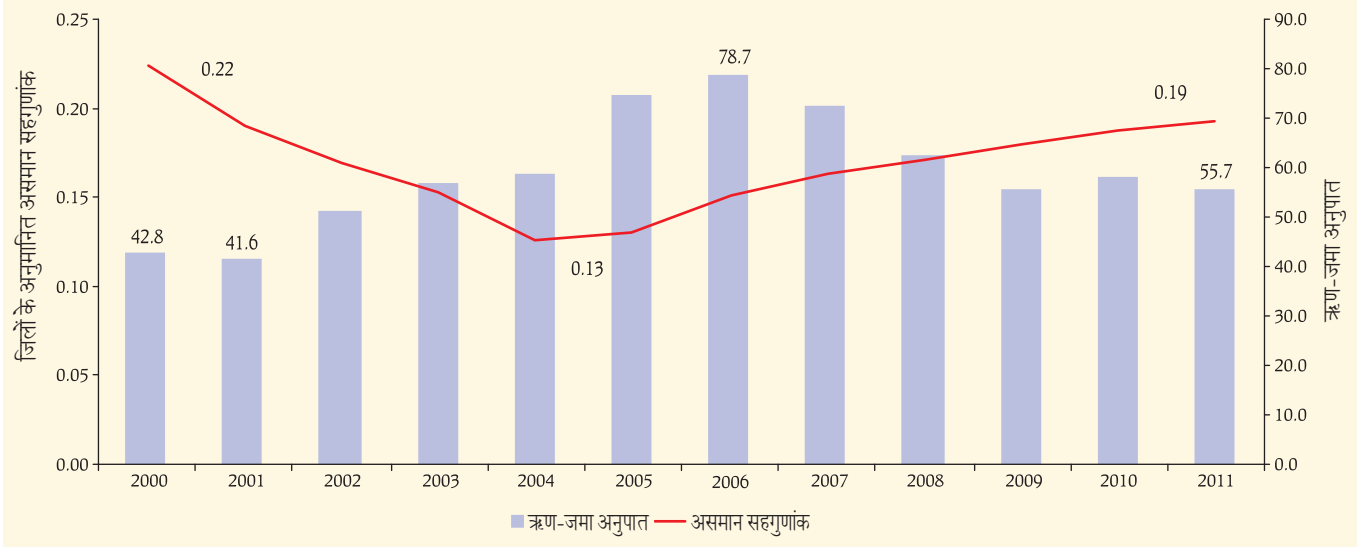

[2] चट्टोपाध्याय, सदन कुमार (2011), *फाइनेन्शिएल इनक्लूजन ऑफ इण्डिया: एक केस स्टडी ऑफ वेस्ट बंगाल, भा.रि.बैं वर्किंग पेपर सं. 8/2011.*

दूसरा, लोगों में वित्तीय उत्पाद और सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके समाज के सभी वर्गों को वित्तीय साक्षारता प्रदान करना।

तीसरा, ब्याज दर और शाखा लाइसेन्स के उदारीकरण के जरिए अधिक विनियामक प्रोत्साहन। बैंकों को इस बात की पूरी छूट दी गई कि वे अपने अग्रिमों का मूल्य निर्धारित करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के ऋण वाणिज्यिक वस्तु बन सकें। औपचारिक ऋण की कम उपलब्धता और साहूकार के पास जाने की मजबूरी को देखते हुए लागत के बजाए ऋण का उपलब्ध हो जाना बड़ी बात है। बैंकों को 1,00,000 से कम जनसंख्या वाले स्थानों पर शाखाएं खोलने की भी छूट दी गई है।

चौथा, तकनीकी और नवोन्मेषी सुपुर्दगी माध्यमों का प्रयोग करना ताकि भारी संख्या में होने वाले छोटे-छोटे लेनदेनों की लागत को कम किया जा सके। इस प्रयास में बैंकों के प्राधिकृत एजेन्टों द्वारा वित्तीय उत्पाद और सेवाओं को घर-घर सुपुर्दगी प्रदान करने के लिए कारोबार प्रतिनिधि मॉडल शुरू करना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करने के लिए इलेक्ट्रानिक लाभ अंतरण को शामिल किया गया है।

इस दिशा में, मार्च 2012 के अंत तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए गए हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान बैंकिंग व्याप्ति में पर्याप्त प्रगति हुई है (सारणी 2)। अगला कदम 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने का है। इसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां (एसएलबीसी) समयबद्ध तरीके से इन गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर रही हैं। सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि बैंक 3-4 किलोमीटर की दूरी पर 8-10 बीसी इकाइयों के समूह के लिए भौतिक शाखाएं स्थापित करे।

ओडिशा में वित्तीय समावेशन

अब मैं यहां पर ओडिशा के वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) की प्रगति पर चर्चा करना चाहता हूँ।

पहला, ओडिशा में बैंकों ने मार्च 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 1,877 बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इनमें से 54 गांवों में भौतिक शाखाओं की स्थापना की गई है, 7 गांवों में अति लघु शाखाएं, 1,740 गांवों में बीसी की नियुक्तियां और 83 गांवों में मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है। मार्च 2013 तक बैंकों द्वारा 200 अतिरिक्त भौतिक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त 1600 से 2000 तक की जनसंख्या वाले 1,502 गांवों की पहचान की गई है जहां मार्च 2013 तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

दूसरा, मार्च 2012 तक, 6 लाख से अधिक नो फ्रिल खाते खोले गए और 24 वित्तीय साक्षरता परामर्श केन्द्रों की स्थापना की गई। तीसरा, 2011-12 के दौरान 10 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड

सारणी 4: वित्तीय समावेशन योजना के तहत हुई प्रगति

	विवरण	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012
1	लगाए गए ग्राहक सेवा स्थानों की संख्या	33,042	57,329	95,767
2	बैंकिंग आउटलेट-गांव >2000-उप जोड़	27,353	54,246	82,300
3	बैंकिंग आउटलेट-गांव >2000-शाखाएं	19,572	20,691	22,706
4	बैंकिंग आउटलेट- गांव>2000-बीसी	7,687	33,181	58,113
5	बैंकिंग आउटलेट- गांव>2000-अन्य प्रणाली	94	374	1,481
6	बैंकिंग आउटलेट- गांव<2000-उप जोड़	26,905	45,937	65,234
7	बैंकिंग आउटलेट- गांव<2000-शाखाएं	1,903	1,971	1,995
8	बैंकिंग आउटलेट- गांव<2000-बीसी	24,997	43,957	62,242
9	बैंकिंग आउटलेट- गांव<2000-अन्य प्रणाली	5	9	997
10	बैंकिंग आउटलेट- सभी गांव - शाखाएं	21,475	22,662	24,701
11	बैंकिंग आउटलेट- सभी गांव - बीसी	32,684	77,138	120,351
12	बैंकिंग आउटलेट- सभी गांव - अन्य प्रणाली	99	383	2,478
13	बैंकिंग आउटलेट- सभी गांव - जोड़	54,258	100,183	147,534
14	बीसी के जरिए शामिल किए गए शहरी क्षेत्र	433	3,757	5,875
15	नो फ्रिल खाते (संख्या मिलियन में)	49	74	103
16	नो फ्रिल खाते में राशि (राशि ₹ बिलियन)	43	57	93
17	ओवरड्राफ्ट वाले नो फ्रिल खाते (संख्या मिलियन में)	0.1	0.6	1.5
18	ओवरड्राफ्ट वाले नो फ्रिल खाते (राशि ₹ बिलियन में)	0.1	0.2	0.6
19	केसीसी (संख्या मिलियन में)	18	20	22
20	केसीसी (राशि बिलियन में)	987	1,324	1,781
21	जीसीसी (संख्या मिलियन में)	0.5	1.1	1.3
22	जीसीसी (राशि बिलियन में)	6	21	25
23	आईसीटी आधारित खाते - बीसी के जरिए (संख्या मिलियन में)	13	30	52
24	आईसीटी आधारित खाते - लेनदेन (राशि मिलियन में)	19	64	120
25	आईसीटी आधारित खाते - लेनदेन (राशि ₹ बिलियन में)	6	55	88

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

जारी किए गए । इसके अतिरिक्त 8000, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड और 1000 आर्टिशन क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। चौथा, 2011-12 के दौरान 58,000 स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा प्रदान की गई।

नीतिगत चुनौतियां

अब मैं समष्टि आर्थिक नीतिगत चुनौतियों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ।

पहला, यद्यपि ओडिशा की आर्थिक व्यवस्था में संरचनागत परिर्वतन दिखाई देते हैं किन्तु हाल के वर्षों में संवृद्धि में सुस्ती आई है। ओडिशा की अर्थव्यवस्था को पुन:विकास की गति पाने की जरूरत है ताकि न सिर्फ इसकी प्रति व्यक्ति आय में सुधार हो बल्कि यह राष्ट्रीय औसत को भी पार करे।

दूसरा, यद्यपि अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है फिर भी कृषि की पैदावार स्थिर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बार-बार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती रही है। इसलिए कृषि पैदावार, जो राष्ट्रीय मानक के अनुसार कम है, में सार्वजनिक निवेश करके और बेहतर जल प्रबंधन पद्धतियों को अपनाकर इसे बढ़ाने के सामूहिक प्रयास किए जाएं।

तीसरा, मध्यवर्ती समय के दौरान, शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक सार्वजनिक निवेश के जरिए ग्रामीण जनसंख्या की कुशलता का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे कृषि से इतर लाभकारी रोजगार और जीविका के अवसर पा सके। इससे अधिक यंत्रीकरण और आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे कृषि की पैदावार और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

चौथा, कृषि क्षेत्र से उद्योग और सेवा क्षेत्र में आए श्रम बल का प्रबंधन करना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। खनिज संपदा की पर्याप्तता को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि वहां कच्चे माल से संबंधित उद्योग विकसित होंगे। तथापि, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मूल्य बढ़ाने पर जोर देने के साथ-साथ पारदर्शी और पर्यावरण को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए।

पांचवा, राज्य में बहुमूल्य धरोहर और सामरिक लोकेशन होने के कारण यहां देशी और अंतरराष्ट्रीय पर्यटनों को विकसित करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। इस संबंध में भुवनेश्वर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाकर और निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता के साथ अतिथि सेवा क्षेत्र (होस्पिटेलिटी) को विकसित करने से सेवा क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। राज्य में अन्य कई एयरपोर्ट विकसित करके कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है।

छठा, भुवनेश्वर जैसे कई शहरी क्षेत्रों को ज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित किए जाए जो न सिर्फ राज्य की विकासशील अर्थव्यवस्था की कुशलता की जरूरत को पूरा करेगा बल्कि राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति पूल में भी अपना योगदान कर सकेगा। इससे सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रोद्योगिकी जैसे उद्योगों के लिए जरूरी प्रशिक्षित मानव शक्ति को विकसित करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

सातवां, राज्य के वित्तीय क्षेत्र में वाणिज्यि बैंकों की भरमार है। इसीलिए बैंकिंग सेवाओं का विस्तार व्यापक आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी है। इस संदर्भ में, बैंकिंग व्याप्ति की संख्यात्मक उपलब्धि, नो फ्रिल खातों की संख्या बढ़ने के रूप में प्रतिबिंबित होती है, इन खातों को सक्रिय ऋण और इनमें जमा लेनदेनों के जरिए सार्थक वित्तीय समावेशन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों की प्रधानता और प्राकृतिक आपदाओं की अधिक आवृत्ति होने को देखते हुए, समूह-उधार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में बैक, राज्य सरकार और रिज़र्व बैंक सभी को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है; बैंक यह सुनिश्चित करें कि बीसी सक्रिय हैं और भौतिक शाखाएं भी धीरे-धीरे बढ़ रही हैं; राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि सामाजिक लाभ का अंतरण बैंक खातों के जरिए हो रहा है; और रिज़र्व बैंक राज्य में वित्तीय समावेशन की कार्य-योजना की प्रभावी ढंग से निगरानी और सक्रिय तालमेल बनाए।

निष्कर्ष

मुझे लगता है कि पिछले दशक के बाद ओडिशा ने निम्न स्तर से शुरुआत करके तीव्र आर्थिक प्रगति की है। इस प्रक्रिया में कई सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार हुआ है किन्तु वे अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम हैं। संसाधनों के वरदान और राज्य की रणनीतिगत स्थिति को देखते हुए, आर्थिक गतिविधि, जो हाल के वर्षों में धीमी हो गई है, को गति प्रदान करने के लिए यह सही समय है। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक व्यय और उद्योग तथा सेवाओं में निजी निवेश को सक्रिय प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इस प्रकिया में, बैंक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।